

दैनिक

रोकथोक लेखनी

(R)

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

बीएमसी ने यातायात पुलिस से अंधेरी में गोखले पुल को बंद करने को कहा



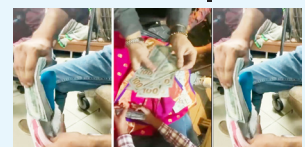
मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने पुलिस को पश्चिम रेलवे मार्ग के ऊपर से गुजर रहे अंधेरी स्थित गोखले पुल को वाहन यातायात के लिए तत्काल बंद करने के लिए कहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। संयोगवश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय विधायक अमित सताम ने इस पुल के 'खतरनाक स्थिति' में होने को लेकर एक नवंबर को महानगरपालिका के प्रमुख इकबाल सिंह चहल को पत्र लिखा था। अतिरिक्त निगम आयुक्त पी वेलारासू ने कहा, "हमने (यातायात पुलिस को) इस पुल को वाहन यातायात के लिए तत्काल बंद करने के लिए कहा है।" इस पुल का एक हिस्सा 2018 में अकस्मात ढह गया था जिससे दो लोगों की मौत हो गयी थी। अधिकारियों ने माना कि

इस पुल के बंद होने से यातायात जाम लगेगा क्योंकि यह पूर्व एवं पश्चिम को जोड़ने वाला एक अहम सेतु है। उन्होंने कहा कि वाहन यात्रियों को राहत प्रदान करने के लिए वैकल्पिक मार्गों को अंतिम रूप दिया जाएगा। सताम ने अपने पत्र में कहा है कि पुल के बीएमसी हिस्से का (मरम्मत)

दुबई जा रहा भारतीय परिवार मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, जब्त किए गए करीब चार करोड़ रुपये

मुंबई : दुबई जाने वाले एक परिवार को सीमा शुल्क विभाग की टीम ने मुंबई के एयरपोर्ट पर रोका। परिवार के तीन सदस्य थे। तीनों के सामान की जांच की गई, जिसमें 4,97,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 4.1 करोड़ रुपये) की विदेशी मुद्रा जब्त की गई। तीनों यात्रियों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस ने

काम पूरा होने के करीब है, जबकि रेलवे के ऊपर से गुजर रहे हिस्से का (मरम्मत) काम अभी शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, "बीएमसी के परामर्शदाता एससीजी कंसलटेंसी सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान पुल बहुत खतरनाक स्थिति में है और किसी भी पल कोई हादसा हो सकता है, इसलिए इसे तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए।" उन्होंने चहल से रेलवे मार्ग के ऊपर पुलिस के हिस्से के मरम्मत कार्य के लिए निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया तेजी से पूरा करने को भी कहा है।



48 घंटे के भीतर एक साल की बच्ची के अपहरण का मामला सुलझाया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

बांबे हाई कोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाई कोर्ट करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज!

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाई कोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाई कोर्ट करने की मांग वाली याचिका वीरवार को खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा कि ये कानून निमाताओं को तय करने के लिए मुद्दे हैं। इसे यहां लाने के लिए आपके लिए किस मौलिक अधिकार का पूर्वाग्रह है।

पुलिस थाने के अंदर वीडियो शूट करना अपराध नहीं
बांबे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने गत दिनों कहा था कि आधिकारिक गोपनीयता कानून के तहत पुलिस थाना प्रतिबंधित जगह के रूप में शामिल नहीं है, इसलिए पुलिस थाने के अंदर वीडियो शूट करना अपराध नहीं हो सकता है। इस साल जुलाई में जस्टिस मनीष पिटाले व वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने मार्च, 2018 में एक



पुलिस स्टेशन के अंदर एक वीडियो रिकार्ड करने के लिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत एक रवींद्र उपाध्याय के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया है। पीठ ने अपने आदेश में निषिद्ध स्थानों पर

जासूसी से संबंधित ओएसए की धारा 3 और धारा 2 (8) का उल्लेख किया व कहा कि अधिनियम में एक पुलिस स्टेशन को विशेष रूप से निषिद्ध स्थान के रूप में वर्णित नहीं किया गया।

ठाणे के पूर्व जज ने दायर की थी याचिका

प्रेट्र के मुताबिक, ठाणे के वीपी पाटिल ने यह याचिका दायर की थी। उन्होंने 26 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। उन्होंने अधिकारियों को महाराष्ट्र अनुकूलन कानून (राज्य और समवर्ती विषय) आदेश के एक खंड के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश देने की भी मांग की थी। पाटिल ने कहा कि अन्य राज्यों के संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे अपने हाई कोर्ट के नाम उन राज्यों के नाम के अनुसार बदलें, जहां वे स्थित हैं। उन्होंने कहा कि 'महाराष्ट्र' शब्द का उच्चारण महाराष्ट्रियन के जीवन में विशेष महत्व को दर्शाता है। इसके उपयोग को हाई कोर्ट के नाम पर भी अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए।

एक वर्षीय बच्ची को तरस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया



मुंबई : मुंबई पुलिस ने 48 घंटे के भीतर एक साल की बच्ची की चोरी की वारदात को सुलझा दिया। मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फंसलकर ने बताया कि मामले में बच्ची को सुरक्षित छुड़ा लिया गया है और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक प्राथमिक जांच में पता चला है कि बच्ची को भीख मांगने के लिए चुराया गया था। हालांकि, इस गिरोह की तीसरी कड़ी की अभी तलाश है, जिस तक

दोनों महिलाएं उस बच्ची को पहुंचाने वाली थीं। मुंबई पुलिस ने एक सप्ताह में बच्चा चोरी की ये दूसरी वारदात को सुलझाया है। पुलिस के मुताबिक, 30 अक्टूबर की रात को फुटपाथ पर रहने वाली एक महिला की एक साल की बच्ची चोरी कर ली गई। सांताक्रुज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने के साथ मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को भी जांच की जिम्मेदारी दी गई।

क्राइम ब्रांच डीसीपी संग्राम सिंह निशानदार के मुताबिक, यूनिट 9 ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालकर आरोपी महिला का फोटो निकाला और फिर आसपास की बस्ती में उस फोटो की पहचान करनी शुरू की।

मॉल में हादसा, स्लाइड करने के दौरान 3 साल की मासूम की गई जान, मचा हड़कंप...!

मुंबई : घाटकोपर ईस्ट इलाके से एक बेहद ही चौकाने वाली घटना सामने आई है। घाटकोपर के नीलयोग मॉल के किड्स जोन में खेलने के दौरान 3 साल की एक मासूम बच्ची अचानक बेहोश हो गई। इसके बाद फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने एडीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 30 अक्टूबर रविवार की शाम को हुई है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। रिकॉर्ड सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 साल की दलीशा



वर्मा किड्स जोन के स्लाइडर से स्लाइड करते हुए तेजी से नीचे की तरफ आती है और आते ही नीचे खड़ी अपनी मां से लिपट जाती है। इसके बाद कुछ सेकंड तक वह अपनी मां से बात करती है और बेहोश हो जाती है। उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता

है, जहां उसकी इलाज शुरू होने से पहले ही मौत हो जाती है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच करने के बाद पुलिस ने इस मामले में एडीआर दर्ज कर आगे की तहकीकात कर रही है।

पुलिस के मुताबिक घटनास्थल पर मौजूद बच्ची के माता-पिता ने भी इस मामले में कोई शक नहीं जताया है। लेकिन फिर भी पुलिस घटना की तह तक जाने में जुटी हुई है। वहीं इस मामले में किड्स जोन की मालकिन भी सामने आईं। उन्होंने बताया कि दलीशा 30 अक्टूबर को शाम 4 बजे

मामले में पुलिस ने एडीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आई थी, 4.15 बजे उसके साथ यह हादसा हुआ। उसे अस्पताल भी ले जाया गया लेकिन उसकी मौत पहले ही हो गई। किड्स जोन की मालकिन ने यह भी दावा किया कि उनके यहां स्टाफ को हर महीने बच्चों को संभालने की ट्रेनिंग दी जाती है और यहां पर लापरवाही का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता।



संपादकीय / लेख



फैसल शेख

(प्रधान संपादक)

जिद का धुआं

दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत कई राज्यों में प्रदूषण से फिर लोगों का दम घुटने लगा है। मंगलवार को दिल्ली की आबोहवा में वायु की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में जा पहुंची। सांस व अन्य गंभीर रोगों से जूझ रहे लोगों के लिये तो यह स्थिति जहरीली है ही, आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका घातक असर पड़ रहा है। धुंध व धुएं की छाया परत से दृश्यता कम होने से सड़क दुर्घटनाओं की भी

आशंका बनी रहती है। इस प्रदूषण की मूल वजह पराली जलाना बताया जा रहा है। यूं तो पराली जलाने की घटनाएं अन्य राज्यों में भी हैं लेकिन पंजाब की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। विडंबना यह है कि पराली प्रबंधन के विकल्पों पर तमाम बहसों व उपायों के बावजूद कोई कारगर समाधान नहीं निकला है। छोटे-छोटे मुद्दों पर आंदोलन छेड़ने वाले किसान इस बात पर संवेदनशील नहीं हैं कि वे कैसे दूसरों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो किसान पराली जला रहे हैं, वे अपने व परिवार के लोगों का भला कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि वे लोगों के जीवन से किस हद तक खिलवाड़ कर रहे हैं। मगर किसान जिद व तल्खी के साथ पराली जला रहे हैं। विडंबना देखिये कि अमेरिका में बैठे नासा के वैज्ञानिक बता रहे हैं कि किस बड़े पैमाने पर खेतों में आग जल रही है। मगर पास के राजनेताओं को यह नजर नहीं आता। वे अपने क्षुद्र राजनीतिक हितों के लिये पराली जलाने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। विडंबना ये है कि किसान जानते हैं कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वे बड़ा वोट बैंक हैं। राजनेता उन्हें छुड़ाने आ जायेंगे। वहीं पराली की आग रोकने में लगे कृषि अधिकारियों की जान सांसत में फंसी है। उन्हें पराली जलाने वालों द्वारा बंधक बनाने की खबरें आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब में पराली जलाना न रोक पाने का ठीकरा उनके सिर फरेक जा रहा है, कई अधिकारी निलंबित किये गये हैं।

पंजाब में इस साल पराली जलाने के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। बीते माह तक राज्य में पराली जलाने के 18 हजार मामले सामने आये हैं जबकि सिर्फ 2700 किसानों पर पराली जलाने पर जुर्माना हुआ है। साथ ही जमीन की रेड एट्री भी सिर्फ 537 की हुई है। इसके बावजूद पंजाब सरकार का इस वर्ष कम संख्या में पराली जलाने की घटनाओं का दावा है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में खासी कमी आई है। सरकार का दावा है कि अक्तूबर माह के अंत तक पराली जलाने के 1925 मामले सामने आए। हरियाणा सरकार ने किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिये प्रति कुंतल धान पर सौ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी है। यह राशि प्रति एकड़ तक एक हजार रुपये निर्धारित की गई है। वहीं पराली की गांठें बनाने पर प्रति कुंतल पचास रुपये की राशि देय है। निस्संदेह, यदि सरकारें इस दिशा में गंभीर प्रयास करें और किसानों को सरल विकल्प व प्रोत्साहन राशि दें तो लाखों लोगों की जीवन डोर बचायी जा सकती है। विडंबना है कि राज्य सरकारों की प्राथमिकता पर्यावरण संरक्षण की नहीं होती है। वे वोटों के लोभ में किसानों के गलत क्रमों पर आंख मूंद लेते हैं। मंगलवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक का 429 के गंभीर स्तर तक पहुंचना समस्या की भयावहता को दर्शाता है। जिसको लेकर राज्य सरकारों की जवाबदेही तय करने की जरूरत है कि क्यों वे किसानों को पराली जलाने से नहीं रोक पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पराली जलाने से ही यह स्थिति खराब होती है। समाज में नागरिकों के गैरजिम्मेदार व्यवहार की भी इसमें भूमिका होती है।

✉ editor@rokhoklehaninews.com

🐦 Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

कैंसर मरीजों के लिए टाटा की नई पहल



मुंबई : टाटा मेमोरियल अस्पताल ने कैंसर के मरीजों के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत कैंसर के मरीजों के लिए केवट खेवइया बनेंगे। ये केवट कैंसर से जूझ रहे मरीजों के इलाज में मदद से लेकर काउंसलिंग की जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। फिलहाल टाटा अस्पताल में अब तक दो बैचों में ६० अभ्यर्थियों को तैयार किया जा चुका है। दूसरी तरफ इंडोनेशिया सरकार को कैंसर पेशेंट नेविगेटर कार्यक्रम के तहत शुरू केवट पहल इतनी भा गई कि उसने हिंदुस्थान के साथ समझौता भी कर लिया है। इस समझौते के तहत इंडोनेशिया में २५ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया जाएगा।

कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, जिसका नाम सुनते ही अमूमन हर कोई चिंता में पड़ जाता है। इसे लाइलाज भी माना जाता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को इससे ग्रसित होने के बारे में देर से पता चलता है। कई रिसर्च सामने आई हैं, जिनके मुताबिक शुरू में इसके होने का पता चल जाए तो इलाज कुछ हद तक संभव हो सकता है। हिंदुस्थान में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और चिंता वाली बात ये है कि इनमें युवाओं की संख्या ज्यादा है। कैंसर का पता चलते ही मरीज हताश और निराश हो जाता है। इसके अलावा टाटा जैसे कैंसर अस्पताल में इलाज कराने पहुंचने पर उन्हें सटीक जानकारी न होने से इलाज कराने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को हल करने के लिए केवट को तैयार किया जा रहा है, जिसे देश से लेकर विदेशों तक विस्तार करने का खाका टाटा अस्पताल ने तैयार किया है।

टाटा मेमोरियल सेंटर के निदेशक डॉ. राजेंद्र बड़वे ने कहा कि मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में हर साल एक लाख लोगों में कैंसर के ९० से १०० नए मरीज सामने आते हैं। साथ ही छोटे शहरों में यह संख्या ६० से ७५ और ग्रामीण में ४० से ४५ है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप में यह आंकड़ा ३०० से ३६० के बीच में है। इनमें से देश में मृतकों की संख्या ५० से ६० और विकसित देशों में ११५ है। उन्होंने कहा कि देश में १०० में से ४० फीसदी मुंह के कैंसर के मामले सामने आते हैं। इसके बाद दूसरे क्रमांक पर ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के मामले हैं। इसी तरह १० फीसदी इंफेक्शन और १५ फीसदी कैंसर मोटापे से होते हैं। डॉ. निशु सिंह गोयल और डॉ. विनीत सामंत ने बताया कि टाटा मेमोरियल सेंटर ने केवट की स्थापना की है।

पति ने पीटा, तीन माह के भ्रूण की मौत, एक महीने बाद दर्ज किया मामला



ठाणे : भिवंडी के भोईवाड़ा इलाके में २६ वर्षीय महिला के साथ बहुत ही नाइसाफी का मामला सामने आया। महिला को उसके पति ने पीटा उस दौरान महिला के पेट में मौजूद तीन माह के भ्रूण की मौत हो गई। पीड़ित महिला और उसके परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज करने में करीब एक महीने का समय लगा दिया। साथ ही स्व. इंदिरा गांधी उपजिला अस्पताल में जांच मशीन नहीं होने के कारण महिला को मुंबई के एक अस्पताल में जाना पड़ा। लगभग तीन दिनों तक मां पेट में मृत भ्रूण को लेकर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही।

बता दें कि पीड़िता के मुताबिक उसके पति और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे।

ब्लू व्हेल रोजाना निगल रही 1 करोड़ से ज्यादा प्लास्टिक के टुकड़े



मुंबई : ब्लू व्हेल के आकार से तो हम सब वाकिफ हैं। ब्लू व्हेल को पृथ्वी पर सबसे बड़ी मछली के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार व्हेल हर दिन कई टन भोजन निगलती है। चिंता का विषय तो यह है कि समुद्र में प्रदूषण के छोटे-छोटे कणों की खतरनाक मात्रा के कारण, व्हेल अब भारी मात्रा में प्लास्टिक का सेवन करने को मजबूर है। शोधकर्ताओं ने मंगलवार को अमेरिकी प्रशांत तट से बेलन व्हेल की तीन प्रजातियों ब्लू, फिन और हंपबैक को लेकर एक रिपोर्ट पेश की। बताया गया कि व्हेल एक दिन में कितना माइक्रोप्लास्टिक निगल रही है या निकल सकती है। अध्ययन के अनुसार ब्लू व्हेल प्रतिदिन लगभग १० मिलियन माइक्रोप्लास्टिक के टुकड़े या लगभग ९५ पाउंड ४३.५ किलोग्राम प्लास्टिक निगल रही है, वहीं फिन व्हेल प्रतिदिन ६ मिलियन माइक्रोप्लास्टिक टुकड़े या ५७ पाउंड तक प्लास्टिक निगल रही है। अध्ययन के अनुसार हंपबैक व्हेल प्रतिदिन लगभग ४ मिलियन माइक्रोप्लास्टिक टुकड़े ३८ पाउंड तक प्लास्टिक निगल रही है। जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित अध्ययन के सह-लेखक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के समुद्री जीवविज्ञानी मैथ्यू सावोका ने कहा कि यू.एस. वेस्ट कोस्ट से मध्यम प्रदूषित पानी में बेलन व्हेल अभी भी लाखों माइक्रोप्लास्टिक्स और माइक्रोफाइबर प्रति दिन निगल रही है। शोधकर्ताओं ने १२६ ब्लू व्हेल, ६५ हंपबैक व्हेल और २९ फिन व्हेल के भोजन पर इस रिसर्च को पूरा किया है। शोधकर्ताओं ने इलेक्ट्रॉनिक टैग डिवाइस सक्शन-क्यूप से जानवरों की पीठ तक माप का उपयोग किया गया था, जिसमें एक वैष्टमरा, माइक्रोफोन, जीपीएस लोकेटर और एक उपकरण था।

ट्विटर को 'तबाह' कर देंगे मस्क!

मुंबई : दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के ट्विटर का मालिक बनते ही ट्विटर हिचकोले खाने लगा है। मस्क ने सबसे पहले तो सीईओ पराग अग्रवाल समेत कई कर्मचारियों को निकाल दिया और अब वे ब्लू टिक के लिए शुल्क लगाने जा रहे हैं। मस्क के अनुसार ब्लू टिक (वेरिफाइड) के लिए लोगों को ६६० रुपए (८ डॉलर) प्रति महीना शुल्क अदा करना होगा। इसे लेकर लोगों में भारी नाराजगी है और ट्विटर पर ही लोग मस्क की आलोचना कर रहे हैं। मस्क को भी इस बात का अच्छी तरह पता है, तभी तो उन्होंने ट्वीट किया कि कोई कितना भी कंप्लेन करे, ८ डॉलर तो देना ही पड़ेगा। मस्क के इस कदम से ट्विटर का नुकसान होना तय है क्योंकि लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्री में ही पसंद करते हैं।

गौरतलब है कि कुछ साल पहले ब्लैकबेरी फोन स्टेटस सिंबल था और लोग शुल्क भरने के बाद उस पर ग्रुप चैट करते थे। मगर जैसे ही मुफ्त मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप की एंट्री हुई ब्लैकबेरी की दुकान ही बंद हो गई। अब लोगों का मानना है कि अगर मस्क नहीं माने तो ट्विटर का तबाह होना तय है। लोग दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर मुड़ जाएंगे। बता दें कि ब्लू सब्सक्रिप्शन पर चार्ज लगाए जाने का



क्यास पिछले कई दिनों से चल रहा था मगर अब खुद मस्क ने ही इसका एलान कर दिया है। कंपनी के नए मालिक मस्क ने ब्लू टिक के लिए मंथली चार्ज की जानकारी खुद ट्वीट कर दी है।

एलन मस्क ने ट्वीट कर बताया कि अब ब्लू टिक के लिए यूजर्स को हर महीने ८ डॉलर यानी करीब ६६० रुपए चुकाने होंगे। हालांकि, मस्क ने इस चार्ज के बारे में यह भी साफ किया कि हर देश में वहां की परचेजिंग पावर के हिसाब से इस चार्ज को बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। इस बारे में ट्वीट करते हुए मस्क ने लिखा कि, ट्विटर पर ब्लू टिक किसके पास है किसके पास नहीं, इसका मौजूदा तरीका सामंतवादी है। मस्क ने ट्वीट कर बताया कि अगर कोई यूजर ब्लू टिक के ८ डॉलर दे रहा है, तो ब्लू टिक वालों को रिप्लाई, सर्च और मेशन में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें लंबे वीडियो और ऑडियो पोस्ट करने की सुविधा दी जाएगी। ब्लू टिक यूजर्स को पेवॉल के जरिए ट्विटर के साथ काम करने का मौका मिलेगा।



NCP नेता जयंत पाटिल का शिंदे सरकार पर तंज...!

महाराष्ट्र के बजाय गुजरात की सेवा के लिए बनी गवर्मेंट

महाराष्ट्र : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जयंत पाटिल ने बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को गंवाने के लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और उस पर 'गुजरात की सेवा करने का आरोप लगाया। पुलिस भर्ती को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर यहां राकांपा द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में पाटिल ने यह भी कहा कि टाटा जैसे समूह द्वारा अपनी परियोजना के लिए दूसरे राज्य को चुनना सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है। पाटिल ने कहा, "परियोजनाओं को गुजरात में स्थानांतरित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मूकदर्शक बने हुए हैं। अगर वेदांता-फॉक्सकॉन परियोजना राज्य में आती, तो इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तीन से चार लाख रोजगार पैदा होते।

महाराष्ट्र के पूर्व वित्त मंत्री पाटिल ने कहा कि वेदांता-फॉक्सकॉन के बाद, टाटा कंसोर्टियम और एयरबस



की सैन्य विमान परियोजना भी गुजरात चली गई। राकांपा नेता ने आगे दावा किया, "राज्य में नयी सरकार लाने की साजिश रची गई ताकि (नयी) सरकार महाराष्ट्र से ज्यादा गुजरात की सेवा करे। इस साल जून में शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार गिरने के बाद शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई थी। पाटिल ने राज्य सरकार पर पूर्ववर्ती एमवीए सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न

करने का भी आरोप लगाया। राकांपा नेता ने आरोप लगाया, "हमने पुलिस भर्ती का निर्णय लिया था और वर्तमान की सरकार को केवल इसे लागू करने की जरूरत है, लेकिन वे बाधाएं पैदा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' के पहले पन्ने पर राज्य सरकार के एक विज्ञापन के प्रकाशन को लेकर पाटिल ने कहा कि कोई भी अखबार किसी विज्ञापन को मना नहीं करेगा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अखबार के अंदर क्या

प्रकाशित किया गया है, उसे भी पढ़ना चाहिए। शिंदे नीत सरकार द्वारा राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के लिए आम सहमति बहाल करने के बारे में (जिसे पूर्ववर्ती एमवीए सरकार ने वापस ले लिया था), पाटिल ने कहा कि राज्य पुलिस किसी भी मामले की जांच करने में सक्षम है। उन्होंने कहा, "यह दिखाता है कि सरकार को महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा नहीं है।

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस आरोप पर कि महाराष्ट्र से बाहर जा रही परियोजनाओं पर एक फर्जी विमर्श पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार ने वेदांता के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल से बात करने और सेमीकंडक्टर परियोजना को वापस लाने की कोशिश नहीं की। राकांपा नेता ने कहा, "अगर टाटा जैसा समूह महाराष्ट्र से बाहर जा रहा है, तो यह इस सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है।

विवादों में मीरा-भायंदर शहर का नया डीपी

भायंदर : छह वर्षों के विलंब के बाद हाल ही में प्रकाशित किया गया मीरा-भायंदर शहर का नया डीपी (डेवलपमेंट प्लान) विवादों में घिर गया है। एक तरफ तो प्रत्यक्ष सर्वेक्षण किए बिना वातानुकूलित कमरे में बैठकर डेवलपमेंट प्लान (डीपी) बनाने के आरोप लग रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में 'ईडी' सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा भायंदर-पश्चिम के ग्रामीण किसानों से मेट्रो कारशेड के आरक्षण को हटाने का किया गया वादा भी झूठा साबित हुआ है।



कारशेड आरक्षण को स्थानांतरित करेंगे लेकिन नए डीपी के प्रकाशित होने पर उनका वादा झूठा साबित हुआ है। नए डीपी में मेट्रो कारशेड का आरक्षण जस का तस बना हुआ है।

उत्तन के छह गांवों उत्तन, पाली, चौक, तरोड़ी, डोंगरी और मोर्वा को मनोरंजन और पर्यटन के क्षेत्र में शामिल करने के बाद वहां का विकास पूरी तरह थम गया था। शहर के विकास के साथ इन सभी गांवों का भी सुनियोजित विकास हो, इसके लिए मनपा प्रशासन ने हाल ही में राज्य के शहर विकास विभाग को पत्र भेजकर सरकार से इन गांवों को पुनः मनपा में शामिल करने की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री शिंदे ने इन गांवों को फिर से मनपा में शामिल करने का आदेश दिया था। प्रत्यक्ष में नए डीपी में इन गांवों को नहीं दर्शाया गया है, जिससे इन गांवों के ग्रामीणों सहित मनपा प्रशासन को भी निराशा हुई है।

नवी मुंबई में टर्शियरी प्लांट में शुद्ध किया जा रहा दूषित पानी...!

6 लाख लीटर पानी दिया जा रहा MIDC में



नवी मुंबई : केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत मलनिस्सारण केंद्र में आने वाले दूषित पानी को शुद्ध करने के लिए नवी मुंबई महानगरपालिका द्वारा कोपरखैरणे में टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। जिसमें प्रतिदिन 20 एमएलडी पानी को शुद्ध किया जा रहा है। इस प्लांट में शुद्ध किया गया 6 लाख लीटर पानी तुर्षे एमआईडीसी स्थित 6 कंपनियों में प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। गौरतलब है कि पानी के महत्व को देखते हुए महानगरपालिका द्वारा पानी की बचत करने के लिए कोपरखैरणे और ऐरोली में 20-20 एमएलडी के टर्शियर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। जिसमें दूषित पानी को शुद्ध किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण महानगरपालिका कमिश्नर

राजेश नावेंकर ने कोपरखैरणे प्लांट में किया। इस मौके पर उन्होंने रिसाइकिल किए गए पानी के पूर्ण उपयोग के लिए त्वरित ठोस कदम उठाने का निर्देश महानगरपालिका के जलापूर्ति विभाग को दिया। इस मौके पर महानगरपालिका के शहर अभियंता संजय देसाई, उपयुक्त बाबासाहेब राजले, अतिरिक्त शहर अभियंता मनोज पाटिल, कार्यकारी अभियंता अजय संखे, विजय राउत, कोपरखैरणे के विभाग अधिकारी प्रशांत गावडे और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

औद्योगिक समूहों संपर्क करने का निर्देश
कोपरखैरणे के प्लांट में शुद्ध होकर निकलने वाले पानी को अधिक औद्योगिक समूहों को देने पर महानगरपालिका कमिश्नर नावेंकर

ने जोर दिया है। इसके लिए उन्होंने महानगरपालिका के संबंधित विभाग को ठाणे-बेलापुर एमआईडीसी के औद्योगिक समूहों से संपर्क करने का निर्देश महानगरपालिका के संबंधित विभाग को दिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत बनाए गए इस प्लांट की लागत का 50 प्रतिशत राशि केंद्र और राज्य सरकारों के माध्यम से महानगरपालिका को उपलब्ध कराई गई थी। मौजूदा समय में नवी मुंबई मनपा द्वारा शहर में 7 स्थानों पर सी-टेक तकनीक पर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट सेंटर हैं। जिसमें ट्रीटेड पानी का उपयोग महानगरपालिका क्षेत्र के बगीचे और चौराहों पर लगे पेड़-पौधों और चौकों में बनाए गए फव्वारे के लिए किया जा रहा है। नवी मुंबई महानगरपालिका द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं और गतिविधियां अभिनव हैं और यह हमारे शहर की पहचान है। इसलिए इस पहचान को मजबूत करने के लिए हर मामले में रचनात्मकता का इस्तेमाल करने और शहर की प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

पीएम मोदी ने की घोषणा महाराष्ट्र में 2 लाख करोड़ रुपए के 225 प्रोजेक्ट

मुंबई : वेदांता-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, मेडिसिन डेवाइस पार्क, टाटा एयरबस और सैफ्रन ग्रुप जैसी कंपनियों के महाराष्ट्र के बाहर जाने को लेकर सरकार पर हो रहे विपक्ष के हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा की है। महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए की कुल 225 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में सरकार ने 75 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। जिसको लेकर मुंबई के यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में रोजगार सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे।

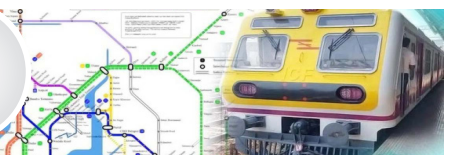


अवसर सृजित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 225 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें से कुछ परियोजनाओं के काम शुरू हो गए हैं कुछ के शुरू होने हैं। महाराष्ट्र में सड़क के लिए 50 हजार करोड़, रेलवे के लिए 75 हजार करोड़ रुपए की निधि दी गई

है। सरकार देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर खर्च कर रही है। जिससे रोजगार के लाखों अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

दोनों विधायकों में पुरानी है जंग!

सरकार स्टार्टअप, लघु उद्योगों को आर्थिक मदद कर रही पीएम मोदी ने कहा कि सरकार स्टार्टअप, लघु उद्योगों को आर्थिक मदद कर रही है। जिससे युवाओं को अपना कौशल्य दिखाने का अवसर मिल रहा है। सरकार के प्रयासों से दलित, आदिवासी, महिलाओं को समान रूप से रोजगार का अवसर उपलब्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों में 8 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ी गई हैं। उन्हें साढ़े पांच लाख करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई है। इस ग्रुप से जुड़ी महिलाएं दूसरी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं।



मुंबई में पकड़ी गई हेरोइन मामले में वांछित तीन ड्रग तस्कर गिरफ्तार

पंजाब : पंजाब पुलिस ने तीन हाई प्रोफाइल ड्रग तस्कर काबू किए हैं। सभी को गुरदासपुर से पकड़ा गया है। यह तीनों जुलाई में मुंबई में न्हावा शेवा पोर्ट पर पकड़ी गई 72 किलोग्राम हेरोइन मामले में वांछित थे। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि तीनों अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करों में शामिल हैं।

पंजाब पुलिस और ATS मुंबई के सहयोग से जुलाई 2022 को मुम्बई के न्हावा शेवा पोर्ट से पकड़ी गई 363 करोड़ रुपए की हेरोइन मामले में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी गुरदासपुर पुलिस ने मिली एक इनपुट के आधार पर की है। इस गिरफ्तारी के बाद विदेश से हेरोइन मंगवाकर देश के विभिन्न राज्यों में तस्करों के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है।

DGP पंजाब गौरव यादव ने बताया कि तीनों आरोपी पंजाब में बड़े पैमाने पर सीमा पार और अंतर-राज्यीय नशीले पदार्थों की तस्करों में सक्रिय रूप से शामिल थे। पंजाब पुलिस के SSOC



विंग ने जुलाई 2022 को इनपुट दी थी कि मुंबई के न्हावा शेवा पोर्ट पर खेप पहुंचाई गई है। इसके लिए अट्रक का सहयोग किया गया। दुबई से मुंबई पहुंचे एक कंटेनर को खोला गया तो उसमें से

72.5 किलो हेरोइन बरामद की गई थी। जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू 363 करोड़ रुपए आंकी गई थी। जांच में सामने आया कि यह कंटेनर जनवरी 2022 को दुबई से मुंबई पोर्ट पर पहुंचा था,

लेकिन इसे कोई लेने ही नहीं पहुंचा, लेकिन इसकी सूचना SSOC विंग पंजाब को लग गई। दरअसल, पकड़े गए ये तीनों आरोपी अपने साथियों के साथ खेप को पोर्ट से निकालने के सही समय का इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद इस खेप को देश के विभिन्न राज्यों तक सप्लाइ किया जाना था। गुरदासपुर कोर्ट में किया जाएगा पेश पकड़े गए तीनों तस्करों को आज दोपहर कोर्ट में पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा।

महिला पत्रकार का अपमान करने पर संभाजी भिड़े पर भड़की सुप्रिया सुले



मुंबई : श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान के संस्थापक एवं प्रमुख संभाजी भिड़े अपने एक बयान के चलते विवाद में फंस गए हैं। हाल ही में संभाजी भिड़े ने एक महिला

पत्रकार से बात करने से इनकार कर दिया। क्योंकि महिला ने अपने बिंदी नहीं लगाई थी। इस वजह से अब विवाद शुरू हो गया है। संभाजी भिड़े को महिला आयोग की ओर से नोटिस भेजा गया है। इसके बाद अब सुप्रिया सुले ने संभाजी भिड़े पर एक 'कविता' के जरिए भी निशाना साधा है। हाल ही में सुप्रिया सुले ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हेरंब कुलकर्णी की कविता शेयर कर संभाजी भिड़े के बयान पर निशाना साधा है। इस कविता के जरिए सुप्रिया सुले ने संभाजी भिड़े को खरीखोटी सुनाई है।

मुंबई में किशोरी से दुष्कर्म...!

दबाव बढ़ा तो रीवा में छोड़कर भाग गया था



मुंबई : रीवा जिले के मनगवां थाना अंतर्गत दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने दो साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसने जान पहचान की लड़की से रेप किया था। वह इतना शातिर था कि अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखता था। ऐसे में मनगवां पुलिस की कई टीमों महाराष्ट्र के मुंबई व पुणे खोज कर आ चुकी थीं। कुछ माह पहले एसपी नवनीत भसीन ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। इसके बाद मनगवां पुलिस ने जान पहचान के लोगों का फोन नंबर जुटाकर गांव में मुखबिर लगाए। साथ ही बाहर रहने वाले रिश्तेदारों की कुंडली तैयार की। अंततः साइबर सेल एवं अन्य तकनीकी माध्यम से आरोपी को पुणे में गिरफ्तार कर लिया है।

मनगवां थाना प्रभारी निरीक्षक

जेपी पटेल ने बताया कि एक आरोपी दो वर्ष पहले नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर महाराष्ट्र ले गया। वहां किशोरी के साथ रेप किया। पीड़िता के विरोध करने पर रीवा आया। यहां किशोरी को छोड़कर फरार हो गया था। लड़की के बयान पर आरोपी शिवकुमार साकेत निवासी नवागांव कोठार के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376(2) का प्रकरण दर्ज कर तलाश की जा रही थी।

विवेचना के दौरान पता चला कि आरोपी शातिर है। मोबाइल का उपयोग ही नहीं करता था। बीते वर्ष भी आरोपी की तलाश में पुलिस टीम महाराष्ट्र गई थी, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा था। अंततः एसपी ने 10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर नए तरीके से विवेचना के आदेश दिए। टीम में कई लोगों को लगाया गया। जो धीरे धीरे इनपुट जुटाती रही।

रामदास आठवले ने BJP-MNS की संभावित युति पर दिया यह बयान

ठाणे : केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि अगर बीजेपी आगामी महानगरपालिका चुनाव जीतने के लिए राज ठाकरे की मनसे के साथ गठबंधन करती है, तो इससे बीजेपी की छवि खराब होगी। केंद्रीय मंत्री आठवले आचार्य अत्रे 50 साल के दलित पैथर आंदोलन पर आधारित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के लिए रंगमंदिर आए थे। इस दौरान उन्होंने यह वक्तव्य दिया। साथ ही उन्होंने एक्ट्रेस जूही चावला के ट्वीट पर तंज



करते हुए कहा कि यदि जूही चावला को मुंबई की हवा से बदबू आ रही है तो उन्हें मुंबई छोड़ देना चाहिए। आगामी महानगरपालिका चुनाव में बीजेपी और मनसे के गठबंधन के सवाल के जवाब में मीडिया से

बात करते हुए आठवले ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से राज ठाकरे के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उत्तर भारतीयों पिटाई और उनका किया गया विरोध और लाउडस्पीकर जैसे कुछ मुद्दों के खिलाफ हूँ क्योंकि देश के अधिकांश हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का काफी दबदबा है। ऐसे में अगर ऐसी स्थिति में मनसे के साथ गठबंधन किया जाता है तो बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और बीजेपी की छवि खराब होगी।

आठवले ने कहा कि चूंकि बालासाहेब की शिवसेना, बीजेपी और रिपाई आठवले गुट मुंबई महानगर क्षेत्र प्राधिकरण की महानगर पालिकाओं और नगरपरिषदों में एक साथ लड़ेंगे, इसलिए इस गठबंधन में मनसे की कोई जरूरत नहीं है। आठवले ने अभिनेत्री जूही चावला के ट्वीट पर कहा कि मुंबई में अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स का घर है।

झोपड़ियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर

केंद्रीय मंत्री आठवले ने प्रो. विट्टल शिंदे द्वारा लिखित पुस्तक दलित पैथर क्रांतिकारी रोहड़ी का विमोचन करते हुए पैथर आंदोलन की यादें ताजा की। साथ ही उन्होंने इस दौरान मुंबई और आसपास के शहरों के कई हिस्सों में स्थित झोपड़पट्टियों की समस्याओं को लेकर कहा कि इन समस्याओं को दूर करने को लेकर हमने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा की है। इस समस्या को दूर करने का जल्द प्रयास किया जाएगा।

मुद्रा योजना में 20 लाख करोड़ के ऋण वितरित किए गए

महाराष्ट्र प्रमुख लाभार्थियों में से एक : मोदी

मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए केंद्र की मुद्रा योजना के तहत अब तक 20 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र इस योजना के प्रमुख लाभार्थियों में से एक है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 75,000 लोगों को रोजगार देने के लक्ष्य के तहत नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए यहां एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रसारित एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार 'स्टार्ट-अप' और सूक्ष्म उद्योगों को भी मदद मुहैया करा रही है। मोदी सरकार ने अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरुआत की थी जिसका मकसद गैर-कॉर्पोरेट व गैर-कृषि लघु व सूक्ष्म



उद्यमों को 10 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान करना था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा, "भारत को विकसित देश बनाने में युवाओं की अहम भूमिका है। केंद्र ने 10 लाख रोजगार मुहैया कराने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है और इसी तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने 75,000 लोगों को रोजगार देने की योजना शुरू की है। यह गर्व की बात है कि अधिकतम भर्तियां गृह एवं ग्रामीण विकास विभागों में की जाएंगी।"

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रोत्साहित किया जा रहा है और पिछले आठ साल में, एसएचजी में काम करने वाली आठ करोड़ महिलाओं को 5.5 लाख करोड़ रुपये तक की धनराशि मुहैया कराई गई है। मोदी ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों ने विनिर्माण और रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा के लिए निवेश किया जा रहा है जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75,000 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएं और 50,000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनसे रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।